Content is available at: CRDEEP Journals
Journal homepage: http://www.crdeepjournal.org/category/journals/ijssah/

International Journal of Social Sciences Arts and Humanities
(ISSN: 2321-4147) (Scientific Journal Impact Factor: 6.002)

Full Length Research Paper

भारत में गुणवत्ता शिक्षा पर हालिया चुनौतियाँ और शोध

डॉ कुलदीप[1] और मिथिलेश कुमार[2*]
[1]–सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, साई नाथ विश्वविद्यालय, राँची झारखण्ड
[2]–शोधकर्ता, शिक्षा विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, साई नाथ विश्वविद्यालय, राँची झारखण्ड

ARTICLE DETAILS

Corresponding Author:
मिथिलेश कुमार

Key words:
भारतं गुणवत्ता शिक्षा
चुनौतियाँ शोध

ABSTRACT

भारत में गुणवत्ता शिक्षा पर हालिया चुनौतियों और शोध पर यह अध्ययन विचार करता है कि गुणवत्ता शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है। यह अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करता है और वर्तमान में इस दिशा में किए जा रहे शोधों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह अनुसंधान शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों और भारत के संदर्भ में किए गए प्रयासों का विश्लेषण करता है। यह अनुसंधान यूनेस्को के 2030 दृष्टिकोण से जुड़े उद्देश्यों पर आधारित है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशन, साक्षरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख लक्ष्यों की पहचान की गई है। साथ ही यह भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों जैसे समग्र शिक्षा अभियान और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों का विश्लेषण भी करता है। यह लेख शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मूल्यांकन, निरीक्षण, और निगरानी की प्रक्रियाओं पर भी चर्चा करता है। इसके अतिरिक्त, यह आध्यात्मिकता, नैतिकता और आधुनिक तकनीकी नवाचारों जैसे आईसीटी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा को सुधारने के संभावनाओं पर विचार करता है। कुल मिलाकर, इस शोध में शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने के लिए समग्र दृष्टिकोण के रूप में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के महत्व को रेखांकित किया गया है।

परिचय

गुणवत्ता शिक्षा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और जटिल अवधारणा है, जिसका प्रभाव हर समाज और राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति पर पड़ता है। उच्च शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे देश के विकास की दिशा निर्धारित की गई है। भारत में शिक्षा का दायरा बहुत व्यापक है, लेकिन गुणवत्ता शिक्षा की अवधारणा को साकार करना अभी भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता को सुधारने के लिए ना केवल एक उपयुक्त प्रणाली की आवश्यकता है, बल्कि यह भी जरूरी है कि यह प्रणाली वैश्विक मानकों के अनुरूप हो और समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ हो (गुप्ता और पाटिल, 2010)।

शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने के लिए कई योजनाएँ और पहल की गई हैं, जिनमें यूनेस्को के 2030 एजेंडा में निर्धारित लक्ष्य शामिल हैं। यूनेस्को के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में रचनात्मकता, साक्षरता, संख्यात्मकता के कौशल और सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय तथा पारस्परिक कौशलों का समावेश किया जाना चाहिए (यूनेस्को, 2015)। भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हालाँकि, इन सुधारों का उद्देश्य केवल शिक्षा का विस्तार करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता बनी रहे और हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर प्राप्त हो। गुणवत्ता शिक्षा की यह आवश्यकता केवल भारत के

Author can be contacted at: शोधकर्ता, शिक्षा विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, साई नाथ विश्वविद्यालय, राँची झारखण्ड
Received: 12-12- 2024; Sent for Review on: 21 12- 2024; Draft sent to Author for corrections: 30-12-2024; Accepted on: 30-12-2024 2024; Online Available from 30-12-2024
DOI: 10.13140/RG.2.2.33554.16324
IJSSAH: 2024-18/*© 2024 CRDEEP Journals. All Rights Reserved.*

लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 1990 के दशक में हुए विश्व शिक्षा मंच पर यह मान्यता दी गई थी कि शिक्षा के मामले में गुणवत्ता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ताकि छात्रों को न केवल मौलिक पढ़ाई और लेखन कौशल मिले, बल्कि वे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल भी प्राप्त कर सकें (विश्व शिक्षा मंच, 2015)। इस संदर्भ में, शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता का बार–बार उल्लेख किया गया है, ताकि शिक्षा संस्थान अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सकें और वैश्विक मानकों पर खरा उतर सकें। इस शोध का उद्देश्य इन सभी पहलुओं पर विचार करना है और यह पहचानना है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने के लिए वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों की क्या स्थिति है। यह शोध शिक्षा में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मूल्यांकन, निरीक्षण, और निगरानी की प्रक्रियाओं पर भी केंद्रित है। साथ ही, यह आध्यात्मिकता, नैतिकता और नई तकनीकी विधियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (प्ब्ज) का उपयोग करके गुणवत्ता शिक्षा को सुधारने की संभावनाओं पर विचार करता है (सारिनेन, 2010)। इस शोध में शिक्षा में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के दृष्टिकोण को भी विशेष महत्व दिया गया है, जो गुणवत्ता सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।

गुणवत्ता की परिभाषा

'गुणवत्ता' शब्द लैटिन शब्द से आया है, जिसका अर्थ है 'किस प्रकार का'। इसके विभिन्न अर्थ और संदर्भ हैं। हालांकि यह उच्च शिक्षा पर बहसों में एक प्रसिद्ध शब्द बन चुका है, फिर भी इसकी सटीक परिभाषा का अभाव है (बॉल, 1985य निगवेकर, 1996य सैलिस, 1996)। भले ही हम यह जानते हों कि गुणवत्ता मौजूद है, लेकिन हम इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। गुणवत्ता एक आधुनिक अवधारणा नहीं है। यह प्राचीन काल से उपयोग में रही है। उदाहरण स्वरूप, मिस्रवासियों ने पिरामिडों के निर्माण के लिए श्सिद्धि के चिन्हश के रूप में गुणवत्ता की अवधारणा का इस्तेमाल किया था (एलशेन्नावी, 2004)। हालांकि, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता पर ध्यान 1980 के दशक के शुरूआत में दिया गया। यह औद्योगिक और वाणिज्यिक सेटिंग्स से लिया गया था। उन दिनों, लोग अकादमिक गुणवत्ता की चर्चा केवल अमूर्त शब्दों में करते थे। कुछ संस्थानों में इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाता था, जैसे हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड। 1990 के दशक में, कुछ शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता की कमी के बारे में उल्लेख किया गया, बिना यह परिभाषित किए कि गुणवत्ता से क्या मतलब था और किस प्रकार का उपचार आवश्यक था। 2000 के दशक में, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आंदोलन को गति मिली, क्योंकि इसे अपरिहार्य माना जाने लगा। इस दौरान, गुणवत्ता की नाजुक प्रकृति पर सवाल उठाए गए और नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता को सुझाव दिया गया (सारिनेन, 2010)।

आज भी श्गुणवत्ताश शब्द को सटीक रूप से परिभाषित करना कठिन है क्योंकि यह एक अदृश्य, तुलनात्मक और निरंतर विकसित होने वाली अवधारणा है। कई लोगों के लिए, यह सत्य या सौंदर्य की तरह एक निराकार अवधारणा है। जैसे सौंदर्य देखने वाले की आँखों में होता है, वैसे ही गुणवत्ता विभिन्न हितधारकों की मानसिकता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि यह मसनेपअम और अपरिभाषित बनी रहती है। इसे अक्सर एक तुलनात्मक शब्द के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह न केवल विभिन्न लोगों के लिए अलग–अलग अर्थ रखता है, बल्कि एक ही व्यक्ति इसे विभिन्न समयों में अलग तरीके से देख सकता है। जैसे बदलती हुई परिस्थितियाँ, वैसे ही यह अवधारणा भी विकसित होती रहती है। उदाहरण के लिए, एक समय में, उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को पूर्वनिर्धारित मानकों या बेंचमार्क्स की पूर्ति के संदर्भ में आंका जाता था। ध्यान आमतौर पर उच्च शिक्षा पर इसके परिवर्तक रूप में इनपुट्स और आउटपुट्स के संदर्भ में केंद्रित होता था। अक्सर इसके पीछे के राजनीतिक और सांकेतिक आधारों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। हालांकि अब गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता ऑडिट, गुणवत्ता प्रबंधन, गुणवत्ता मान्यता और मूल्यांकन पर बहुत कुछ लिखा गया है, परंतु गुणवत्ता की अवधारणा पर बहुत कम लिखा गया है। यह अभी भी एक अत्यधिक व्यक्तिपरक और मूल्य–युक्त शब्द बना हुआ है, जैसे सत्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, निष्पक्षता आदि। हालांकि यह अत्यधिक वांछनीय है, इसे पूरी तरह से व्यावहारिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

गुणवत्ता शिक्षा क्यों आवश्यक है

ईएफए ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2005 के अनुसार, यह कहा गया है कि शिक्षा में सार्वभौमिक भागीदारी की प्राप्ति पूरी तरह से उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। यदि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया, तो लोग शिक्षा में रुचि

खो देंगे। इस घटना का एक उदाहरण ग्रामीण भारत के स्कूलों में देखा जा सकता है, जहाँ भारतीय सरकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए सभी भौतिक बुनियादी ढांचे प्रदान करने की पूरी कोशिश के बावजूद ड्रॉपआउट्स की संख्या बढ़ रही है। यह सिर्फ इन ग्रामीण स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा की कमी के कारण है। इसलिए, शिक्षा प्रणाली में बच्चों की स्थायित्व बनाए रखना गुणवत्ता शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक बिंदु है। अगर यह सवाल पूछा जाए कि अगर गुणवत्ता शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो क्या होगा, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब गुणवत्ता शिक्षा क्यों एक आवश्यकता है। भारत में श्टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेप्युटेशन रैंकिंग्सश की टॉप 100 सूची में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। यह लगभग अन्य दक्षिण एशियाई या अफ्रीकी देशों के लिए भी समान है। वर्तमान समाज एक बाजार आधारित समाज है जहाँ गुणवत्ता श्बाजारश में बने रहने के लिए मुख्य तत्व है। यह शिक्षा के लिए भी कड़ा सत्य है। शिक्षा गुणवत्ता एक गतिशील, बहुआयामी अवधारणा है, जो न केवल शैक्षिक मॉडल और परिणाम को संदर्भित करती है, बल्कि संस्थागत मिशन और लक्ष्यों, साथ ही प्रणाली या उप–प्रणाली के विशिष्ट मानकों से भी संबंधित है। यह मानवता की उस प्राथमिकता से जुड़ी है जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों पर तरजीह देती है। हालांकि शिक्षा को उत्पाद से नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह आजकल एक वस्तु बन चुकी है। इसलिए, इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा की स्थिति और गुणवत्ता

उच्च शिक्षा और उसका महत्व भारत में

भारत में उच्च शिक्षा ने स्वतंत्रता के बाद देश को गरीबी और अपर्याप्त विकास से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने एक ओर पितृसत्तात्मक और श्रेणीबद्ध समाज में सामाजिक गतिशीलता प्रदान की और दूसरी ओर आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय विकास को भी बढ़ावा दिया। संस्थापकों ने हमेशा शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया, भले ही संसाधनों की कमी थी। इसे 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वाहन' के रूप में देखा गया (मुखर्जी, अज्ञात)। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ाने को प्राथमिकता दी। हालाँकि, हाल ही में इसका ध्यान उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता पर केंद्रित हुआ है, ताकि वैश्वीकरण और तकनीकी नवाचारों के मद्देनजर इन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उपयुक्त बनाया जा सके। भारत शिक्षा हब बनने की आकांक्षा रखता है, जो छात्रों को नवीनतम ज्ञान, कौशल और कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए योग्य बनाने का काम करता है। यह न केवल मस्तिष्क और हृदय के मौलिक मूल्यों को समाहित करने की आवश्यकता है, बल्कि सही आधार और उपयुक्त दृष्टिकोण प्रदान करने की भी आवश्यकता है। आज, भारत में उच्च शिक्षा न केवल आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय विकास में योगदान करती है, बल्कि यह अपने आप में एक बिलियन डॉलर का उद्योग बन चुकी है, और इस प्रकार गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है (गुप्ता और पाटिल, 2010)।

गुणवत्ता बनाम समानता

दरअसल, उच्च शिक्षा के मासिफिकेशन (विस्तार) के साथ, हम गुणवत्ता आश्वासन की आवश्यकता में वृद्धि देख रहे हैं, खासकर जब भारत 'उभरती अर्थव्यवस्था' और 'विश्व शक्ति बनने की प्रक्रिया में' अपनी स्थिति को देखते हुए एक शैक्षिक हब बनने की आकांक्षा रखता है। जैसे कई अन्य वस्त्रों और सेवाओं में, हम 'पहुँच और समानता' से 'गुणवत्ता और विविधता' की ओर ध्यान केंद्रित होते हुए देख रहे हैं। पहले जहां गुणवत्ता की अवधारणा में समानता की प्राप्ति की कोशिशें शामिल थीं, आज इसका जोर विविधता पर है, क्योंकि इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के हितों की सेवा के लिए गुणवत्ता की स्वाभाविक शर्त माना जाता है।

"शैक्षिक कार्यक्रम की कुल गुणवत्ता न केवल उन छात्रों की शैक्षिक और व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित होती है, जो नामांकित हैं, बल्कि उस पूरी छात्र समूह की विशेषताओं से भी प्रभावित होती है जो एक सामान्य शैक्षिक अनुभव साझा करते हैं।... विशेष रूप से एक आवासीय कॉलेज सेटिंग में, बहुत सी शिक्षा अनौपचारिक रूप से होती है,... दोनों लिंगों के छात्रों के बीचय विभिन्न राज्यों और देशों सेय जिनकी रुचियाँ, प्रतिभाएँ और दृष्टिकोण विस्तृत हैंय और जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से एक–दूसरे से भिन्नताओं से सीख सकते हैं और अपनी सबसे गहरी धारणाओं को फिर से जांचने के लिए एक–दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं।... लोग ज्यादा नहीं सीखते जब वे केवल अपने जैसे लोगों से घिरे होते हैं।"

असल में, गुणवत्ता की अवधारणा ने 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और उच्च शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के बाद एक नया अर्थ और महत्व प्राप्त किया। उच्च शिक्षा संस्थानों के गुणवत्ता और मानकों की निगरानी की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे विश्व स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। सामान्य रूप से, गुणवत्ता का मतलब छात्रों की आवश्यकताओं और उम्मीदों को पूरा करना है, एक ओर जहाँ वे ग्राहकों के रूप में हैं, और दूसरी ओर, बाजार और अन्य हितधारक हैं (यूजीसी, 2003)। आज यह आवश्यक हो गया है कि विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा दी जा रही उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि श्पैसे के बदले मूल्यश औरध्या श्समय के बदले मूल्यश को उचित ठहराया जा सके। लेकिन यह एक बड़ी चुनौती है कि समानता के आधार पर पहुंच को विस्तारित किया जाए और साथ ही गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखा जाए।

भारत में गुणवत्ता और समानता

भारत में, गुणवत्ता की अवधारणा को 'समानता' बनाम 'गुणवत्ता' के रूप में नहीं देखा जा सकता। बल्कि हमें इसे 'समानता और गुणवत्ता दोनों' के रूप में देखना होगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के पूर्व निदेशक एच. ए. रंगनाथ (2011) का सुझाव है कि "उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि कम योग्य छात्रों का उत्पादन किया जाए," बल्कि इसका मतलब है "भिन्न–भिन्न प्रेरणाओं और रुचियों वाले छात्रों तक पहुंच बनाना।" यह मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के तेजी से विस्तार और विविध स्वभाव के कारण है कि हमें 'विश्वसनीय आश्वासन' की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसने भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की विश्वसनीयता, विपणन, वैधता और स्वीकार्यता को सुधारने के लिए गुणवत्ता लागू करने को अनिवार्य बना दिया है। यही कारण है कि बाहरी संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन ने एक नया अर्थ प्राप्त किया है। जबकि इन संस्थाओं की क्रियाएँ राष्ट्रीय नीतियों और अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा निर्देशित होती हैं, कई विकास जैसे छात्रों की संख्या में तीव्र वृद्धि या गिरावट, वित्त पोषण नीतियों में बदलाव, और लाभकारी निजी और विदेशी संस्थाओं की भागीदारी, गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं (हार्वे, 2006)।

लक्ष्य और विधि

गुणवत्ता शिक्षा को लागू करने में चुनौतियाँ

संक्षेप में कहा जा सकता है कि गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

1.विश्व मामलों का उचित और शांतिपूर्ण तरीके से प्रबंधन।

2.मानवता का निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में स्थानांतरण।

3.मानवता को भविष्य में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्याओं से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाना।

गुणवत्ता शिक्षा की गारंटी कैसे दी जाए?

गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम यह जानें कि गुणवत्ता शिक्षा क्या है। यदि यह जान लिया जाए कि हमें क्या प्रदान करना है, तो इसे प्रदान करने का तरीका स्पष्ट हो सकता है। यूनेस्को के विजन 2030 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा का स्पष्ट विचार किया जा सकता है। यह यूनेस्को के सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत चौथा लक्ष्य है। 2015 में विश्व शिक्षा मंच के अनुसार "गुणवत्ता शिक्षा रचनात्मकता और ज्ञान को बढ़ावा देती है, और साक्षरता और संख्यात्मकता के मौलिक कौशल के साथ–साथ विश्लेषणात्मक समस्या समाधान और अन्य उच्च–स्तरीय संज्ञानात्मक, पारस्परिक और सामाजिक कौशल की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। यह नागरिकों को स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जीने, सूचित निर्णय लेने और स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों का जवाब देने के लिए आवश्यक कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण भी विकसित करती है।"

इस चौथे लक्ष्य के लिए सात लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो सभी के लिए समावेशी और गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनभर के लिए सीखने को बढ़ावा देने के लिए हैं। इनमें– प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की मुफ्त शिक्षा, गुणवत्ता पूर्व–प्राथमिक शिक्षा तक समान पहुंच, तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच, वित्तीय सफलता के लिए प्रासंगिक कौशल वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, शिक्षा में सभी भेदभाव को समाप्त करना, सार्वभौमिक साक्षरता और संख्यात्मकता, और सतत विकास और वैश्विक नागरिकता के लिए शिक्षा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त तीन अन्य कारक हैं जो

इन लक्ष्यों का हिस्सा हैं और वे हैं– सुरक्षित और समावेशी स्कूल, छात्रवृत्तियाँ और योग्य शिक्षक। अब गुणवत्ता शिक्षा की गारंटी देने के लिए इन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है।

गुणवत्ता शिक्षा के लिए उचित मूल्यांकन

गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की पहली और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वर्तमान शिक्षा की गुणवत्ता का सही मूल्यांकन किया जाए ताकि यह पता चल सके कि सुधार की आवश्यकता किस क्षेत्र में है और किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक बार मूल्यांकन पूरा हो जाए तो फिर गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई जा सकती है। इसलिए, मूल्यांकन प्राथमिक चुनौती है जिसे हल किया जाना चाहिए और इसके लिए हमें उचित और वैज्ञानिक निरीक्षण और निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है।

गुणवत्ता शिक्षा के लिए उचित निरीक्षण, निगरानी और समग्र शासन

एक प्रमुख समस्या यह है कि शिक्षा क्षेत्र में उचित शासन का अभाव है। यह वर्तमान परिदृश्य में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। शैक्षिक संस्थानों के लिए उचित मार्गदर्शन के साथ निरीक्षण और अभिभावक निगरानी की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र के निरीक्षण और शासन संस्थानों को पर्याप्त निगरानी और प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए ताकि वे गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हों और आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण में मान्य बने रहें। अन्यथा, यदि वे गुणवत्ता शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं तो वे समाप्त हो जाएंगे।

आध्यात्मिकता, नैतिकता, और गुणवत्ता शिक्षा

आज की दुनिया एक भौतिकवादी दुनिया है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचता है। समाज या दुनिया के बारे में सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक परिणाम है, जो केवल लोगों को दौड़ में धकेलता है। इस प्रक्रिया में जीवन में शांति और सामंजस्य नहीं होता। इसलिए, इसका एकमात्र समाधान है समय की परखी आध्यात्मिकता, नैतिकता और आचार, जो गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करेंगे और बदले में गुणवत्ता शिक्षा बिना प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में दौड़ने के मानसिक शांति को सुनिश्चित करेगी। प्राचीन भारत में गुरु–शिष्य परंपरा का अस्तित्व था। उस समय कोई गुणवत्ता समस्या नहीं थी क्योंकि सभी शिक्षक गुणवत्ता वाले थे और जो वे सिखाते थे, वह गुणवत्ता शिक्षा थी। साथ ही, छात्रों के पास अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार अपने स्वयं के शिक्षक चुनने का विकल्प था।

आईसीटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग

गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए विचार प्रक्रिया में नवाचार होना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन के साथ तकनीकी क्षेत्र में नवाचार शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा वरदान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकी नवाचारों जैसे ऐप–आधारित शिक्षा, वर्चुअल शिक्षा और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आंशिक वास्तविकता इन शैक्षिक विधियों को बढ़ावा देने में सहायक हैं। इन तकनीकों की मदद से वर्तमान शिक्षण अनुभवों को और अधिक अनुकूल और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों से पूरित किया जा सकता है। चूंकि ये दो–तरफा संचार और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। लेकिन केवल ऊपर दिए गए तरीके सहायक नहीं होंगे, बल्कि एक एकीकृत प्रणाली की आवश्यकता है और इसलिए इस समय की आवश्यकता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।

शिक्षा में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट

गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर यह है कि उपलब्ध संसाधनों के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा का उचित प्रबंधन किया जाए और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के रूप में समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए। यह गुणवत्ता शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा। टोटल क्वालिटी की अवधारणा, जिसे 1950 के दशक में प्रोफेसर डब्ल्यू. एडवर्ड्स डेमिंग द्वारा पेश किया गया, को शैक्षिक संस्थानों के हर संगठन में लागू किया जा सकता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत में गुणवत्ता शिक्षा के दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य लगभग प्राप्त हो चुका है। फिर भी, भारत के पास टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेप्युटेशन रैंकिंग्स 2017 में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की

सूची में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। इसलिए, भारत में गुणवत्ता शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान इस लक्ष्य की ओर एक कदम है। यह भारतीय सरकारी योजना प्राथमिक से लेकर उच्च अध्ययन तक, कौशल विकास, शिक्षक शिक्षा और उन्मुखीकरण के विकास में मदद करेगी। 2030 तक, यह योजना शिक्षा में लिंग और अन्य भेदभाव को समाप्त करने, युवाओं को पर्याप्त साक्षरता, संख्यात्मकता, तकनीकी कौशल और सतत विकास के लिए ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। लेकिन यहां उचित निगरानी और जवाबदेही की समस्या एक बड़ी समस्या है, जिसे यदि समय रहते नहीं ठीक किया गया तो यह घातक साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

गुणवत्ता शिक्षा का भविष्य

भारत में गुणवत्ता शिक्षा का भविष्य उज्जवल और आशाजनक दिखाई देता है, क्योंकि देश में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं। शिक्षा नीति, प्रौद्योगिकी का उपयोग, और समावेशी दृष्टिकोण को अपनाकर भारत अपनी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली और भी सशक्त हो रही है। इसके अलावा, तकनीकी नवाचारों और डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव से शिक्षा का विस्तार और पहुंच भी बढ़ेगी। विशेष रूप से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता , वर्चुअल कक्षाएं और मोबाइल–आधारित शिक्षा जैसी सुविधाओं के उपयोग से छात्रों को अधिक व्यक्तिगत और सुलभ शिक्षा मिल सकेगी। इसके साथ ही, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार और व्यावसायिक कौशल के विकास पर जोर दिया जाएगा, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी। समाज के विभिन्न वर्गों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समावेशी नीतियों को लागू किया जाएगा, ताकि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत अपनी शिक्षा प्रणाली में लगातार सुधार करता रहेगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास संभव हो सकेगा। अंततः, गुणवत्ता शिक्षा का भविष्य भारत में सिर्फ शैक्षिक सुधारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण योगदान देगा। यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय छात्र भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें और देश वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सके।

संदर्भ

बॉल, सी. जे. ई. (1985)। गुणवत्ता क्या है? सी. जे. ई. बॉल (एड.), फिटनेस फॉर पर्पसएसेज इन हायर एजुकेशन (पृ. 96 102)।

बोडेन, आर., – नेडेवा, एम. (2010)। रोजगार के प्रवचन का उपयोगरू विश्वविद्यालयों और स्नातक 'नौकरी योग्यताएँ'। जर्नल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, 25(1), 37 54।

बोवेन, डब्ल्यू., – बोक, डी. (1998)। द शेप ऑफ द रिवररू कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रवेश में जाति के विचारों के दीर्घकालिक परिणाम। प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस।

ब्रिजस्टॉक, आर. (2009)। स्नातक गुण जो हमने अनदेखा कर दिएरू करियर प्रबंधन कौशल के माध्यम से स्नातक रोजगार योग्यताएँ बढ़ाना। हायर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 28(1), 31 44।

कैस्टेल्स, एम. (1997)। द इंफॉर्मेशन एजरू इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। पॉलिटी प्रेस।

चेंग, एम. (2016)। उच्च शिक्षा में गुणवत्तारू पेशेवर अभ्यास के गुण को विकसित करना। सेंस पब्लिशर्स।

चर्च, सी. एच. (1988)। सत्यापन के गुण। स्टडीज इन हायर एजुकेशन, 13(1), 27 43।

क्रॉफर्ड, एफ. डब्ल्यू. (1991)। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ख्पेपर प्रस्तुति,। क्वालिटी बाय डिग्रीज सम्मेलन, ऐस्टन विश्वविद्यालय, यूके।

क्रेमिन, सी. (2010)। कभी भी पर्याप्त योग्य नहींरू बॉस की इच्छाओं को पूरा करने की (अ)संभाव्यता। ऑर्गनाइजेशन, 17(2), 131 149।

क्यूलन, आर. (1992)। विश्वविद्यालय संदर्भ में गुणवत्ता प्रबंधनरू क्या मापा जा सकता है और क्या मापना चाहिए? विक्टोरियन पोस्ट–सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन।

डेग्रीस, सी. (2017)। डिजिटल अर्थव्यवस्था में कार्य की दुनिया को आकार देना। म्ज्न् थ्वतमेपहीज ठतपमि 01(जनवरी)।

ड्यू, जे. (2009)। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मुद्दे। जर्नल फॉर क्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, 32(1), 49।

एलशेन्नावी, ए. (2004)। नए युग में गुणवत्ता और गुणवत्ता इंजीनियरों के लिए ज्ञान का शरीर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड बिजनेस एक्सीलेंस, 15(5), 603 614।
गुप्ता, ए. (2000)। भूमिका निजीकरण के पाररू एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। मैकमिलन।
गुप्ता, ए. (2006)। भारत और अमेरिका में उच्च शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाईरू एक तुलनात्मक अध्ययन। ब्रैम रिसर्च एंड ऑक्जेश्नल पेपर सीरीज, 10.06।
गुप्ता, ए. (2008)। 21वीं सदी में शिक्षारू विश्वविद्यालय से आगे देखना। शिप्रा पब्लिकेशन्स।
गुप्ता, ए., – पाटिल, जे. (2010)। भारतरू राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का योगदान। एम. मार्टिन (एड.), समावेशी और गुणवत्ता आश्वासनरू दो विचारों का विवाह (पृ. 145 173)। यूनेस्को।
हैरिंगटन, एच. जे. (1988)। एक्सीलेंसरू द आईबीएम वे। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल।
हार्वे, एल. (2006)। गुणवत्ता आश्वासन का प्रभावरू बाहरी गुणवत्ता एजेंसियों के प्रतिनिधियों के बीच एक चर्चा का अवलोकन। क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, 12(3), 287 290।
हार्वे, एल., – ग्रीन, डी. (1993)। गुणवत्ता को परिभाषित करना। एसेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन हायर एजुकेशन, 18(1), 9 34।
होल्म्स, एल. (2001)। स्नातक रोजगार योग्यताएँ पर पुनर्विचाररू श्स्नातक पहचानश दृष्टिकोण। क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, 7(2), 111 119।
बसु, एस. (2020, सितंबर 2)। 63 भारतीय विश्वविद्यालय 2021 के टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के लिए पात्र हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स, कोलकाता।